



राज. नं. एल. डब्ल्यू./एन. पी. 896

साहसंस् नं० डब्ल्यू पी०-41

साहसंस् ट पोस्ट एंटे कन्सिशनल पी

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 23 फरवरी, 1998

फाल्गुन 4, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 425/सवह-वि-1-1 (क)-15-1997

लखनऊ, 23 फरवरी, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 10 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 का अप्रति संशोधन करने के लिए

अधिनियम

चूंकि इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में रुड़की विश्वविद्यालय की एक शानदार विरासत और परम्परा रही है और उसने एक प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कर ली है;

और चूंकि विश्वविद्यालय को उत्कर्ष के केंद्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उसकी विद्या परिषद् और वित्त समिति का गठन करने और उसकी सिनेट और सिडीकेट को पुनर्गठित करने के लिए और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को सुकर तथा दक्षतर बनाने के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट में अन्य संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे विनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना, द्वारा इस निमित्त नियत करे।

संयुक्त प्रारम्भ ऐवम्
संख्या 9 सन्
1948 की धारा
2 का प्रतिस्थापन

2--सड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) ऐक्ट, 1947 की, जिसे धारा मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"2--इस ऐक्ट में,--

परिभाषाएँ (क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) 'शैक्षणिक विभाग (एकेडेमिक डिपार्टमेंट)' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग से है जिसमें ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिसकी परिणति स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में होती है;

(ग) 'शैक्षणिक केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी ऐसे विद्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, संस्थान या ऐसी ही किसी संस्था से है जिसमें अनुसंधान, शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य किया जाता हो, किन्तु जो खण्ड (ख) के अधीन न आता हो;

(घ) 'अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य किसी शैक्षणिक विभाग या शैक्षणिक केन्द्र के अध्ययन बोर्ड से है जो रेगुलेशन के अनुसार गठित किया गया हो;

(ङ) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी संकायाध्यक्ष से है;

(च) 'निदेशक या समन्वयकर्ता' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार इस रूप में नियुक्त शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक या समन्वयकर्ता से है;

(छ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(ज) 'शैक्षणिक विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष से है;

(झ) 'छात्रालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त निवास की इकाई से है;

(ञ) 'रजिस्टर्ड ग्रेजुएट' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिडीकेट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से है;

(ट) 'रेगुलेशन' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन सिडीकेट द्वारा बनाये गये रेगुलेशन से है;

(ड) 'नियम' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिडीकेट द्वारा बनाये गये नियम से है;

(ड) 'अध्यापक (टीचर)' का तात्पर्य प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हो;

(द) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन स्थापित सड़की विश्वविद्यालय से है।"

धारा 3 का
संशोधन

3--अब अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(1) विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो, और सिनेट, सिडीकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति के सदस्य जो विश्वविद्यालय में तत्काल ऐसी व्यवस्था कर रहे हों, वे सड़की विश्वविद्यालय नामक एक निमित्त विकास समिति होगा।"

धारा 4 का
संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(एक) खण्ड (2) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेगे, अर्थात्--

"(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो या कुछ शिक्षा विश्वविद्यालय में और कुछ किसी ऐसी संस्था में प्राप्त की हो जिसकी विश्वविद्यालय न इन निमित्त स्वीकृति प्रदान की हो; या

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त स्वीकृत किसी संस्थान में अनुसंधान कार्य किया हो; या”;

(दो) खण्ड (6) में शब्द “प्रोफेसरो” के पश्चात् शब्द “एसोसियेट प्रोफेसरो, असिस्टेंट प्रोफेसरो” बढ़ा दिये जायेंगे;

(तीन) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, बिक्री, दान, बन्धक या तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये पट्टे के रूप में नहीं करेगा।”

5—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

धारा 7-क का
बढ़ाया जाना

“7-क—(1) विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिये विश्व-विद्यालय की एक पुनर्विलोकन समिति होगी।
पुनर्विलोकन समिति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में नौ सदस्य होंगे जो चांसलर द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की हो, नामजद किये जायेंगे।

(3) पुनर्विलोकन समिति के सदस्य चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसी सुविधायें और मानदेय प्राप्त करेंगे जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।

(4) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट समिति उत्तर प्रदेश बड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगी और अपनी रिपोर्ट चांसलर को प्रस्तुत करेगी जो उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ऐक्ट के अधीन समीचीन और आवश्यक समझे।”

6—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

धारा 10 का
प्रतिस्थापन

“10—(1) चांसलर, वाइसचांसलर को नियुक्त न्यूनतम तीन ऐसे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों की सूची में से करेगा जिन्हें कोई वाइसचांसलर ऐसी कमेटी मनोनीत करे जिसमें इंडियन नेशनल अकेडेमी आफ इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट या इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के प्रेसिडेंट और राज्य सरकार के नियुक्त किये हुये दो अन्य सदस्य सम्मिलित हों। वाइसचांसलर ऐसे निबन्धनों पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये अपने पद पर आरुढ़ रहेगा, जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) जहां छुट्टी पर जाने या रोगग्रस्त होने या किसी अन्य कारण से वाइसचांसलर का पद अस्थायी रूप से खाला हो जाय, और—

(एक) ऐसी रिक्ति दो मास से अधिक की अवधि के लिये है, वहां प्रो-वाइस-चांसलर यदि कोई नियुक्त हो, या यदि कोई प्रो-वाइस-चांसलर न हो या प्रो-वाइस-चांसलर भी अनुपस्थित हो तो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम प्रोफेसर दो मास की अवधि की समाप्ति तक या वाइस-चांसलर के पद की रिक्ति भरने तक या प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो, के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, वाइस-चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा;

(दो) ऐसी रिक्ति दो मास से अधिक अवधि के लिये है, वहां चांसलर किसी उपयुक्त इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् को वाइस-चांसलर के पद पर छः मास से अधिक अवधि के लिये, जो समय-समय पर एक वर्ष की कत अवधि तक के लिये, जिसमें मूल आदेश में नियत अवधि भी है, बढ़ाई जा सकती है, नियुक्त कर सकता है।”

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11 का
संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द “सिंडिकेट का मेम्बर और उसका चेयरमैन होगा और” के स्थान पर शब्द “सिंडिकेट का मेम्बर और विद्या और वित्त समिति का चेयरमैन होगा और” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द “सिनेट और सिंडिकेट” के स्थान पर शब्द “सिनेट, सिंडिकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति” रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का
प्रतिस्थापन8--मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी
अर्थात्--

"12--(1) वाइस-चांसलर, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के ज्येष्ठतम प्रोफेसरों में से एक को प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रो-वाइस-चांसलर, प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रो-वाइस-चांसलर, वाइस-चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसी सुविधाएँ और ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा, जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।

(5) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसे विषयों में, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, वाइस-चांसलर की सहायता करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा सीधे या प्रत्यायोजित किये जायें और वाइस-चांसलर की अनुपस्थिति में वाइस-चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।"

धारा 13 का
संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "सिनेट और सिंडीकेट के सेक्रेटरी को हैसियत से काम करेगा" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिंडीकेट, वित्त समिति और विद्या परिषद् के सेक्रेटरी को हैसियत से काम करेगा और नियमों द्वारा निर्धारित रीति से नियुक्त किया जायगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का
संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 15 में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(2-क) विद्या परिषद्;

(2-ख) वित्त समिति।"

धारा 16 का
प्रतिस्थापन

11--मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी
अर्थात्--

"16--(1) सिनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

सिनेट

श्रेणी-एक-पदेन-सदस्य :--

(एक) चांसलर;

(दो) वाइस-चांसलर;

(तीन) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो;

(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो;

(पाँच) समस्त संकायाध्यक्ष;

(छः) समस्त शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष और समस्त शैक्षणिक क्षेत्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता;

(सात) रजिस्ट्रार;

श्रेणी-दो-आजीवन सदस्य :--

(आठ) तीन से अधिक व्यक्ति, जिनको चांसलर नाम से इस कारण आजीवन सदस्य नियुक्त करे कि उन्होंने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान या शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त की है या उनकी प्रशंसनीय सेवा की है;

(नौ) ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके उद्देश्यों के लिये कम से कम दस लाख रुपये दान दिया है;

(दस) ऐसे समस्त व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को आजीवन सदस्य हों;

श्रेणी-तीन-संसद और राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि:--

(ग्यारह) लोक सभा के दो सदस्य जिन्हें लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जायेगा ;

(बारह) राज्य सभा का एक सदस्य जिसे राज्य सभा के सभापति द्वारा नामजद किया जायेगा ;

(तेरह) राज्य विधान सभा के चार सदस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ;

(चौदह) राज्य विधान परिषद् के दो सदस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ;

श्रेणी-चार--रजिस्टर्ड प्रेजुएट:--

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड प्रेजुएटों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायेगा ;

श्रेणी-पांच--अध्यापकों के प्रतिनिधि:--

(सोलह) विश्वविद्यालय के तीस अध्यापक, उनके सिवाय जो किसी अन्य हैसियत में उसके पहले से सदस्य हों, जो अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे । अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय :

परन्तु इस प्रकार एक बार निर्वाचित सदस्य की सदस्यता उस अवधि के दौरान जिसके लिये वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, केवल इस कारण से समाप्त नहीं हो जायेगी कि उसे अध्यापकों की किसी उच्चतर श्रेणी में नियुक्त कर दिया गया था ;

श्रेणी-छ:--शिक्षण-कर्मचारियों के प्रतिनिधि:--

(सत्रह) विश्वविद्यालयों के शिक्षण-कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि जिन्हें वाइस-चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा ;

श्रेणी-सात--राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले अन्य सदस्य, जो निम्नलिखित विशेष हितों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों, श्रयात्:--

(अठारह) इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का एक प्रतिनिधि ;

(उन्नीस) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, निगमों, अनुसंधान, रक्षा (डिफेंस) या अन्य संगठनों के छ: प्रतिनिधि ;

(बीस) निजी क्षेत्र के उद्योगों या संगठनों के तीन प्रतिनिधि ;

(इक्कीस) रेलवे और राज्य सरकार के सिचाई और लोक निर्माण विभागों के एक-एक प्रतिनिधि ;

(बाईस) विश्वविद्यालय के आस-पास के औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि ;

(तेईस) विश्वविद्यालय के आस-पास के अनुसंधान संस्थाओं के दो प्रतिनिधि ;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विषयों (डिस्टिग्लिन) के वृत्तिक निकायों के दो प्रतिनिधि ;

(पच्चीस) राज्य के विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इन्जीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो, कमशः वाइस-चांसलरों, डायरेक्टरों और प्रिन्सिपलों में से तीन प्रतिनिधि ।

(2) उपधारा (1) में, निदिष्ट श्रेणी तीन, चार, पांच और सात के किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त उपधारा में निदिष्ट श्रेणी छ: के सदस्य की पदावधि एक वर्ष होगी जो, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद किये जाने के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो सिनेट का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने पर ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

धारा 18 का
प्रतिस्थापन

अर्थात्—

12—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,

“18—(1) सिडोकेट विश्वविद्यालय की इन्जीन्यूटिंग बाडी होगी।
सिडोकेट

(2) सिडोकेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) वाइस-चांसलर;

(ख) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हों;

(ग) तीन विद्वानाध्यक्ष और शैक्षणिक क्षेत्रों का एक निदेशक या समन्वयकर्ता, जो नियमों द्वारा निर्धारित रीति से अकामुक्त से विद्या परिषद् द्वारा नामजद किये जायेंगे;

(घ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(ङ) अध्यापकों के वी प्रतिनिधि, जिसमें उनके जो कितने अन्य हैतियत में सिडोकेट के पहले से सदस्य हों, जिन्हें सिनेट द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय;

(च) चार व्यक्ति जिन्हें सिनेट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, निर्वाचित किया जायेगा;

(छ) मुख्यात इंजीनियरों और वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) में से दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

(ज) मुख्यात शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों में से दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

(झ) व्यक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सक्षिप्त स्तर से कम का न हो।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (ज), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी, जो यथास्थिति, उनके निर्वाचन या नामजद किये जाने के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो सिनेट का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी, कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।”

धारा 19 का
संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(3) सिडोकेट अध्यापकों की संख्या और ग्रहंताओं और एकजानिनरों की देय फीज के सम्बन्ध में विद्या परिषद् की संस्तुति पर विचार किये बिना कोई विनिश्चय नहीं करेगा।”

नई धारा 19-क,
19-ख, 19-ग,
और 19-घ का
बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

“19-क—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय विद्या परिषद् होगी;

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

श्रेणी-एक—पदेन सदस्य :-

- (एक) वाइस-चांसलर;
- (दो) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;
- (तीन) समस्त शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष;
- (चार) समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकता;
- (पांच) पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामजद एक व्यक्ति;
- (सात) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग का एक नामजद व्यक्ति;
- (आठ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग, या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;
- (नौ) समस्त संकायाध्यक्ष;
- (दस) रजिस्ट्रार;

श्रेणी-दो—अध्यापकों के प्रतिनिधि :-

- (ग्यारह) विश्वविद्यालय के पांच ज्येष्ठतम प्रोफेसर;
 - (बारह) प्रत्येक शैक्षणिक विभाग से दो अध्यापक, जो ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, वाइस-चांसलर द्वारा नामजद किये जायेंगे;
- परन्तु केवल ऐसे लेक्चरर नामजदगी के लिए पात्र होंगे जिन्हें लेक्चरर के रूप में या सजक क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो;

श्रेणी-तीन—चांसलर के नामजद व्यक्ति :-

- (तेरह) वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, टेक्नालाजिस्टों, इंजीनियरों और वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अधिक व्यक्ति;
- (चीदह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिंग या टेक्नालाजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो, क्रमशः वाइस-चांसलरों, निदेशकों और प्रिंसिपलों में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अधिक व्यक्ति;

श्रेणी-चार—औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि :-

- (पन्द्रह) राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के दो प्रतिनिधि;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (बारह), (तेरह), (चीदह) और (पन्द्रह) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उसकी नामजदगी के परवात विद्या परिषद् की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(4) कोई व्यक्ति जो विद्या परिषद् का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी कि उसको पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

19-ख—विद्या परिषद् इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् की रहते हुये—

शक्ति और कर्तव्य

(क) समस्त शैक्षणिक विषयों से संबंधित उपबन्धों की रेगुलेशन में सम्मिलित किये जाने के लिये सिडीकेट की संस्तुति करेगी;

(ख) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी ;

(ग) शैक्षणिक विभाग और शैक्षणिक केंद्रों के सृजन या उद्घाटन या आभेदन या विभाजन के लिये प्रस्तावों पर विचार करेगी और सिडिकेट को उनकी सिफारिश करेगी ;

(घ) विश्वविद्यालय में किये जा रहे या दिए जा रहे शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर का नियंत्रण, विनियमन और अनुरक्षण करेगी ;

(ङ) अध्ययन बोर्ड के कार्य संचालन का समन्वयन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षा की प्रणाली के सम्बन्ध में उनके प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी ;

(च) पी-एच० डी० अभ्यर्थियों के एवजामिनरों की सिफारिशों की संवीक्षा और उनका अनुमोदन करेगी ;

(छ) अध्यापकों की संख्या और उनकी अर्हताओं और एवजामिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में सिडिकेट को सलाह देगी ;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमाओं और डिग्रियों की मान्यता के सम्बन्ध में जैसा कि नियमों और रेगुलेशनों में निर्धारित है, अनुमोदन करेगी ;

(झ) ऐसे विषयों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी जो सिनेट या सिडिकेट द्वारा उसको निदिष्ट किए जाय ;

(ञ) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी, जो इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ;

(ट) विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में सेवायोजक संगठनों द्वारा बदलाव की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए उनसे सम्पर्क बनाये रखेगी ।

19-ग (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

वित्त समिति

(क) चाइस-चांसलर ;

(ख) प्रो-चाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो ;

(ङ) सिडिकेट के संकल्प द्वारा नामजद किए जाने वाले पांच व्यक्ति जिनमें से दो सिडिकेट के सदस्यों से भिन्न ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी शिक्षा और वित्त में रुचि हो ;

(च) मुख्य लेखा अधिकारी ;

(छ) रजिस्ट्रार ।

(2) खण्ड (ङ) में निदिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उसकी नामजदगी के पश्चात् वित्त समिति की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी ;

परन्तु कोई व्यक्ति जो सिडिकेट का सदस्य होने के आधार पर सदस्य हुआ हो इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, सिडिकेट का सदस्य न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा ।

19-घ (1) वित्त समिति इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के

वित्त समिति की अधीन रहते हुये निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग शक्ति और कर्तव्यों का सम्पादन करेगी :—

कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को बनाना और उसके लिए निधि का आवंटन ;

(ख) सहायता अनुदान से भिन्न अतिरिक्त आय के स्रोतों को उत्पन्न करना ;

(ग) विश्वविद्यालय निधि का विनियोजन करने के लिये विश्व-विद्यालय को सलाह देना;

(घ) ऐसे अन्य विषय जो उसे सिंडीकेट द्वारा निर्दिष्ट किये जाय।

(2) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो नियमों के अधीन उसे सौंपे जाय।”

15—मूल अधिनियम की धारा 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्—

धारा 28 और 29 का प्रतिस्थापन

“28—उत्तर प्रदेश उच्चको विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के संकमणकालीन प्रारम्भ होने पर—
उपबन्ध

(एक) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 19-क के उपबन्धों के अनुसार विद्या परिषद् के गठन के लिये कार्यवाही करेगी और जब तक विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय, तब तक विद्या परिषद् के कृत्यों का पालन सिंडीकेट द्वारा किया जायगा;

(दो) सिनेट के सदस्य (जिनसे भिन्न जो विश्वविद्यालय के अफसर या प्राजीवन सदस्य हों) ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा-16 के उपबन्धों के अनुसार सिनेट के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिनेट में पदेन सदस्य, प्राजीवन सदस्य और सिंडीकेट के ऐसे सदस्य होंगे जो खण्ड (तीन) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों;

(तीन) वाइस-चांसलर और प्रो-वाइस-चांसलर से भिन्न सिंडीकेट के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र; किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार सिंडीकेट के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिंडीकेट में वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग और ऐसे सदस्य होंगे जो धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों।

29—(1) चांसलर के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अफसर विश्वविद्यालय अधिभार के दि-सी घन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अफसर के रूप में कार्य करते हुये उसकी उपेक्षा या कदाचरण का प्रत्यक्ष परिणाम हो;

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग से अन्तर्प्रसन्न घनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा निर्धारित की जाय।”

16—मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“31—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश उच्चको विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के अन्तर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

धारा 31 का प्रतिस्थापन

उत्तर प्रदेश अध्यापन मंडल, 23 फरवरी, 1998

18

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक अधिवेशन राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, यथासंभव शीघ्र रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश अध्यापन मंडल अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जितने प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

धारा 32 का
संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "लिटीकेट या लिनेट" के स्थान पर शब्द "लिनेट, लिटीकेट, विल मरमिति या विद्या परिषद्" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,
विशेष सचिव।

No. 425 (2)/XVII-V-1-1(KA)-15-1997

Dated Lucknow, February 23, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Roorkee Vishwavidyalaya (Sanskodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 10, 1998.

THE UTTAR PRADESH ROORKEE UNIVERSITY (AMENDMENT)
ACT, 1997

(U. P. Act No. 10 of 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Roorkee University Act, 1947.

WHEREAS the University of Roorkee has a glorious heritage and traditions and has acquired an eminent status in the field of Engineering and Science education and research;

AND, WHEREAS it is necessary to constitute and Academic Council and a Finance Committee and reconstitute the Senate and the Syndicate of the University and to make other amendments in the Roorkee University Act for the smooth and more efficient working of the University with a view to develop it as a centre of excellence;

Now, THEREFORE, IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In the Roorkee University Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, for section 2, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 2 of U.P. Act no. 9 of 1948

Definitions "2. In this Act,—

(a) 'Academic Council' means the Academic Council of the University;

(b) 'Academic Department' means a teaching Department of the University in which instructions are imparted leading to Bachelor's or Post Graduate Degree or Diploma;

(c) 'Academic Centre' means a School, a Centre, a Laboratory, an Institute or the like, established by the University, in which research, teaching or training is carried out but which is not covered under clause (b);

(d) 'Board of Studies' means the Board of Studies of an Academic Department or an Academic Centre constituted in accordance with the regulations;

(e) 'Dean' means a Dean appointed in accordance with the regulations;

(f) 'Director or Co-ordinator' means the Director or Co-ordinator of an Academic Centre appointed as such in accordance with the regulations;

(g) 'Finance Committee' means the Finance Committee of the University;

(h) 'Head of the Academic Department' means the Head of an Academic Department appointed in accordance with the regulations;

(i) 'Hostel' means a unit of residence for the students of the University maintained or recognised by the University;

(j) 'Registered Graduate' means a graduate registered according to rules framed by the Syndicate under section 20;

(k) 'Regulation' means a regulation framed by the syndicate under section 21;

(l) 'Rule' means a rule framed by the Syndicate under section 20;

(m) 'Teacher' means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Reader, Lecturer or any other person imparting instructions in the University;

(n) 'University' means the Roorkee University established under this Act."

3. In section 3 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of section 3

"(1) The Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, if any, and the members of the Senate, the Syndicate, the Academic Council and the Finance Committee, for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University of Roorkee."

Amendment of
section 4

4. In section 4 of the Principal Act,—

(i) in clause (2), for sub-clause (a), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

“(a) have pursued a course of study in the University or partly in the University and partly in any institution approved in that behalf by the University; or,

(aa) have carried on research in the University or in any institution approved in that behalf by the University; or”;

(ii) in clause (6), after the word “Professorships,” the words “Associate Professorships, Assistant Professorships,” shall be inserted ;

(iii) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that the University shall not transfer any immovable property by way of sale, gift, mortgage or lease for a period exceeding thirty years, without the previous approval of the State Government.”

Insertion of new
section 7-A

5. After section 7 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

“7-A. (1) There shall be a Review Committee of the University to review the over all performance of the University.

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of nine members to be nominated by the Chancellor from amongst the persons who have excelled in the field of engineering, technology or science.

(3) The members of the Review Committee shall hold office at the pleasure of the Chancellor and shall get such facilities and honorarium as may be prescribed by the rules.

(4) Subject to sub-section (1), the Committee referred to therein shall at the end of every three years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997 independently review the academic performance of the University and submit its report to the Chancellor who may take such actions thereon as he may deem expedient and necessary under the Act.”

Substitution
section 10

6. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“10. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor out of a panel of a minimum of three engineers, scientists or technologists, nominated by a Committee consisting of the President of Indian National Academy of Engineering or President of the Institution of Engineers (India), and two other members appointed by the State Government. The Vice-Chancellor shall hold office on such terms and subject to such conditions as may be prescribed by the rules.

(2) Where any temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reasons of leave, illness or any other cause, and—

(i) such vacancy is for a period not exceeding two months the Pro-Vice-Chancellor, if any, appointed or if there is no Pro-Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor too is absent, the senior-most Professor of the University, shall exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor until the expiry of the period of two months or the vacancy in the office of the Vice-Chancellor is filled or the Pro-Vice-Chancellor, if any, takes over, whichever occurs first;

(ii) such a vacancy is for a period exceeding two months, the Chancellor may appoint any suitable engineer, scientist or technologist to the office of the Vice Chancellor for a term not exceeding six months, which may, from time to time, be extended up to a total period of one year, including the term fixed in the original order."

7. In section 11 of the principal Act,—

Amendment of section 11

(a) in sub-section (1), for the words "Chairman of the Syndicate and" the words "Chairman of the Syndicate, Academic Council, and the Finance Committee and" shall be substituted,

(b) in sub-section (3), for the words "Senate and the Syndicate" the words "Senate, the Syndicate, Academic Council and the Finance Committee" shall be substituted.

8. For section 12 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 12

"12. (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst ten senior most Professors of the University.

(2) The Pro-Vice-Chancellor shall discharge his duties in addition to his duties as Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get such facilities and honorarium as may be prescribed by the rules.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in such matters as may be specified by the Vice-Chancellor, from time to time, shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor and shall in the absence of the Vice-Chancellor exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor."

9. In section 13 of the principal Act, for the words "Senate and the Syndicate" the words "Senate, the Syndicate, the Finance Committee and the Academic Council and shall be appointed in the manner prescribed by rules," shall be substituted.

Amendment of section 13

Amendment of
section 15

10. In section 15 of the principal Act, after clause (2), the following clauses shall be inserted, namely :—

- “(2-a) The Academic Council ;
- (2-b) The Finance Committee”.

Substitution of
section 16

11. For section 16 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“16. (1) The Senate shall consist of the following members,
The Senate namely :—

CLASS I—*Ex-officio* Members :

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (iv) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh, in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (v) all Deans;
- (vi) all Heads of the Academic Departments and all Directors or Co-ordinators of Academic Centres;
- (vii) the Registrar;

CLASS II—Life Members :

(viii) persons not exceeding three appointed by name by the Chancellor to be life members on the ground that they have distinguished in or rendered meritorious service to engineering and technological science or education;

(ix) all persons who have made donations of not less than ten lakh rupees to or for the purposes of the University;

(x) all other persons who are life members on the date of commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997;

CLASS III—Representatives of Parliament and State Legislature :

(xi) two members of the Lok Sabha to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha;

(xii) one member of the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of the Rajya Sabha;

(xiii) four members of Vidhan Sabha of the State to be elected by it;

(xiv) two members of the Vidhan Parishad of the State to be elected by it;

CLASS IV—Registered Graduates :

(xv) ten representatives of the registered graduates of the University to be elected in the manner prescribed by the rules;

CLASS V—Representatives of the Teachers :

(xvi) thirty teachers of the University other than those who are already members in some other capacity, to be elected from amongst themselves. The number of different categories of teacher and the manner of their election shall be such as may be prescribed by rules :

Provided that a member once so elected shall not cease to be a member during the term for which he was so elected merely because he was appointed to any higher category of teachers;

CLASS VI—Representatives of Non-Teaching Employees :—

(xvii) four representatives of the Non-Teaching Employees of the University to be nominated by the Vice-Chancellor;

CLASS VII—Other members to be nominated by the State Government representing the following special interests or fields, namely :—

(xviii) one representative of the Institution of Engineers (India);

(xix) six representatives of the Public Sector Industries, Corporations, Research, Defence or other organisations;

(xx) three representatives of the private sector industries or organisations;

(xxi) one representative each of the Railways and Irrigation and Public Works Departments of the State Government;

(xxii) two representatives of the industrial organisations in the neighbourhood of the University;

(xxiii) two representatives of the research institutions in the neighbourhood of the University;

(xxiv) two representatives of the professional bodies of various disciplines of the University;

(xxv) three representatives from amongst the Vice-Chancellors, Directors and Principals respectively of the Universities, Institutes and Colleges in the State having degree courses in Engineering or Technology.

(2) The term of office of a member of classes III, IV, V and VI referred to in sub-section (1) shall be three years and of a member of class VII referred to in the said sub-section shall be one year, commencing from the date of first meeting of the Senate held after his election or nomination, as the case may be.

(3) A person who became a member of the Senate (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office, shall cease to be such member on ceasing to hold such office notwithstanding that his term, if any, has not expired."

Substitution of
section 18

12. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"18. (1) The Syndicate shall be the Executive Body of the University.

(2) The Syndicate shall consist of the following members, namely :—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;

(c) three Heads of the Department and one Director or Co-ordinator of Academic Centres to be nominated by the Academic Council by rotation in the manner prescribed by the rules;

(d) the Dean of Students Welfare;

(e) nine representatives of teachers, other than those who are already members of the Syndicate in any other capacity, to be elected by the Senate. The number of the different categories of teacher and the manner of their election shall be such as may be prescribed by the rules;

(f) four persons to be elected by the Senate from amongst such of its members as are not in the service of the University;

(g) two persons from amongst eminent engineers and architects not in the service of the University to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed by the rules;

(h) two persons from amongst the eminent educationists and scientists not in the service of the University to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed by the rules;

(i) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary.

(3) The term of office of the members referred to in clauses (c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) shall be three years, commencing from the date of the first meeting of the Syndicate held after his election or nomination, as the case may be.

(4) A person who became a member of the syndicate (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office, shall cease to be such member on ceasing to hold such office, notwithstanding that his term if any, has not expired."

Amendment of
section 19

13. In section 19 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted namely :—

"(3) The Syndicate shall not take any decision in regard to the number and qualifications of teachers and the fees payable to the examiners without considering the recommendations of the Academic Council."

14. After section 19 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

Insertion of new sections 19-A, 19-B, 19-C and 19-D

"19-A (1) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely :—

CLASS I—Ex-officio Members :

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;
- (iii) all Heads of Academic Departments;
- (iv) all Directors or Co-ordinators of Academic Centres;
- (v) the Librarian;
- (vi) one nominee of the University Grants Commission, New Delhi;
- (vii) one nominee of the Department of Education in the Ministry of Human Resource Development, Government of India;
- (viii) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;
- (ix) all Deans;
- (x) the Registrar;

CLASS II—Representatives of Teachers :

- (xi) five senior most Professors of the University;
- (xii) two teachers from each academic Department, nominated by the Vice-Chancellor by rotation in order of seniority :

Provided that only such Lecturers shall be eligible for nomination who have atleast three years experience as Lecturer or in equivalent capacity;

CLASS III—Nominees of the Chancellor :

- (xiii) not more than five persons nominated by the Chancellor from amongst scientists, educationists, technologists, engineers and architects;
- (xiv) not more than five persons, nominated by the Chancellor from amongst the Vice-Chancellors, Directors and Principals respectively of the Universities, Institutes and colleges, having degree courses in engineering or technology.

CLASS IV—Representatives of Industrial or Commercial Organisations :—

- (xv) two representatives of the industrial or commercial organisations, to be nominated by the State Government.

(3) The term of office of a member referred to in clauses (xii), (xiii), (xiv) and (xv) of sub-section (2) shall be three years, commencing from the date of first meeting of the Academic Council held after his nomination.

(4) A person who became a member of the Academic Council (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office shall cease to be such member on ceasing to hold such office, notwithstanding that his term, if any, has not expired.

19-B. The Academic Council shall, subject to the provisions of this Act, the rules and the regulations—
Powers and duties of the Academic Council

(a) recommend to the Syndicate provisions relating to all academic matters for inclusion in the regulations;

(b) supervise and control the admission of students in the University and the examinations of the University;

(c) consider and recommend to the Syndicate, proposals for the creation or abolition or merger or division, of the Academic Departments and Academic Centres;

(d) control, regulate and maintain the standards of instruction, education, training and research carried on or imparted in the University;

(e) co-ordinate the working of Boards of Studies and scrutinize and approve their proposals in regard to the scheme of teaching and examinations in the University;

(f) scrutinize and approve the recommendations of the examiners of Ph. D. candidates;

(g) advise the Syndicate in regard to the number and qualifications of teachers, and the fees payable to the examiners;

(h) approve in regard to the recognition of the certificates, diplomas and degrees of other Universities and Institutions, as prescribed in the rules and the regulations;

(i) consider and make its recommendations on such matters as may be referred to it by the Senate or the Syndicate;

(j) perform in relation to academic matters all such duties as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, the rules and the regulations;

(k) maintain contact with employer organisations with a view to, assess their changing needs for the pattern of education required to be imparted by the University.

19-C (1) The Finance Committee shall consist of the following person namely :—
The Finance Committee

(a) the Vice-Chancellor,

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;

(c) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;

(d) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;

(e) five persons to be nominated by the Syndicate by a resolution, out of whom two shall be the persons other than the members of Syndicate, who have interest in education and finance;

(f) the Chief Accounts Officer;

(g) The Registrar.

(2) The term of the office of members referred to in clause (e) shall be three years commencing from the date of first meeting of the Finance Committee after their nomination :

Provided that a person who became the member by virtue of being a member of the Syndicate shall cease to be such member on ceasing to be a member of the Syndicate, notwithstanding that his term, if any, has not expired.

19-D (1) The Finance Committee shall, subject to the provisions of this Act, rules and the regulations, exercise the following powers and perform the following duties

Powers and duties of the Finance Committee

(a) framing of annual budget of the University and allocation of funds therefor;

(b) generating sources of additional income other than the grant-in-aid;

(c) to advise the University on the investment of University Funds;

(d) such other matters as may be referred to it by the Syndicate.

(2) The Finance Committee shall have such other powers and duties as are assigned to it under the rules."

15. For sections 28 and 29 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Substitution of sections 28 and 29

"28. Upon the commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997—

Transitory provisions

(i) the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement take steps for the constitution of the Academic Council in accordance with the provisions of section 19-A and until the Academic Council is so constituted the functions of the Academic Council shall be performed by the Syndicate;

(ii) The members of the Senate (other than those who are officers of the University or life members) shall cease to hold office as such members and the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement, take steps for the reconstitution of the Senate in accordance with the provisions of section 16 and until such reconstitution of the Senate shall consist of the *Ex-officio* members, the life members and such members of the Syndicate as are nominated by the State Government under clause (iii) of section 16;

(iii) the members of the Syndicate other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office as such members and the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement, take steps for the reconstitution of the Syndicate in accordance with the provisions of section 18 and until such reconstitution the Syndicate shall consist of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Dean of Students welfare, the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department and such members as may be nominated by the State Government to represent the classes referred to in clauses (c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 18.

29. (1) An officer of the University except the Chancellor shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct, while acting as such officer.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed by the State Government by notified order."

Substitution of
section 31

16. For section 31 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"31. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, within a period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997 by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as amended by the said Act of 1997, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both the houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply, as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act."

Amendment of
section 32

17. In section 32 of the principal Act, for the words "Syndicate or the Senate" the words "Senate, the Syndicate, the Finance Committee or the Academic Council" shall be substituted.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.